नंदी ने सदन में पेश किया उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अधिनियम 2025

लखनऊ। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2025 प्रस्तुत किया।

मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार की नीयत और नीति एक रही है। निर्णय और निष्पादन एक रहा है। पहले दिन से ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्री फ्रेंडली ईकोसिस्टम हमारी प्रतिबद्धता रही है। हमने समय समय पर ठोस और प्रभावी निर्णयों के माध्यम से इस दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए हैं।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025 प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह निवेशकों के भरोसे और विश्वास को एक नई मजबूती प्रदान करने वाला प्रासंगिक संशोधन है। भारत सरकार द्वारा जन विश्वास (प्रावधान संशोधन

कहा- निवेशकों के भरोसे और विश्वास को नई मजबूती प्रदान करने वाला प्रासंगिक संशोधन

अधिनियम) 2023 के अंतर्गत 42 केंद्रीय अधिनियमों में अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की शुरुआत की गई है।

उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2025 के अंतर्गत राज्य सूची के 10 अधिनियमों में सुधार किया गया है। इसके साथ ही 14 विभागों के 40 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। कारावास का प्रावधान केवल उन अपराधों के लिए रखा गया है, जो शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं अथवा जीवन को संकट में डालते हैं। जो धोखाधड़ी से किए जाते हैं और नकारात्मक बाह्य प्रभाव पैदा करते हैं। अन्य सभी अपराधों जैसे प्रक्रियात्मक चूक, दस्तावेजीकरण त्रुटियां, या सामान्य उल्लंघन को गैर-आपराधिक बनाया गया है। इनके संदर्भ में दंड स्वरूप केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो

अधिनियमों की सूची जिनमें प्रावधानों को संशोधित किया गया है

- उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय का रेगुलेशन) अधिनियम, 1953
- उत्तर प्रदेश सिनेमा (रेगुलेशन) अधिनियम, 1955
- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959
- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976
- उत्तर प्रदेश मदिरा (आपत्तिजनक विज्ञापनों का नियंत्रण) अधिनियम, 1976
- उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006
- उत्तर प्रदेश भू-जल (प्रबंधन एवं रेगुलेशन) अधिनियम, 2019
- उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवाएं (निवारण) अधिनियम, 2022